

राजस्थान सरकार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन आवेदन पत्र संख्या : 13/2014/जयपुर

मैसर्स सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन-द्वितीय, जोन-द्वितीय, जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम्

मैसर्स शर्मा परिवहन कार्गो मूवर्स (प्रा.) लि.,
बनीपार्क, जयपुर।

.....अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एन.के.बैद,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रार्थी की ओर से

श्री एस.के.जैन,
अधिवक्ता।

.....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.02.2015

निर्णय

1. उक्त परिशोधन प्रार्थना पत्र व्यवहारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1379/2007/जयपुर, में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमें व्यवहारी ने अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2013 में अभिलेख की प्रकट भूल होने के कारण इसे, परिशोधित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-द्वितीय, जोन-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 22.04.1999 को वाहन संख्या डी.आई. एल-617 को दिल्ली से जयपुर की ओर आते हुये "चंदवाजी" पर जांच हेतु, रोका गया। सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनीत माल के संबंध में दस्तावेज चाहने पर, वाहन चालक श्री प्रीतम सिंह द्वारा मैसर्स शर्मा परिवहन कार्गो मूवर्स (प्रा.) लि., जयपुर द्वारा जारी चालान क्रमांक 517 दिनांक 21.04.1999 संलग्न 5 जी.आर. व बिल, मैसर्स भारतीय जनता परिवहन द्वारा जारी चालान क्रमांक 238 संलग्न 4 जी.आर. व बिल, चालान क्रमांक 240 संलग्न 4 जी.आर. व बिल, चालान क्रमांक 242 संलग्न 9 जी.आर व बिल वास्ते जांच प्रस्तुत किये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन चालक से पूछताछ करने पर वाहन चालक ने स्वयम् द्वारा दिये गये बयान में यह प्रकट किया कि वाहन में लदा माल जयपुर में खाली करेगा, सारा माल मैसर्स शर्मा परिवहन कार्गो मूवर्स (प्रा.) लि.,

लगातार.....2

परिशोधन आवेदन पत्र संख्या : 13/2014/जयपुर

जयपुर का होना प्रकट कर, समस्त माल को एच-67, आकड़मार्ग, बनीपार्क, जयपुर में खाली करेगा। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, दस्तावेजों में घोषित प्रेषक व प्रेषिति व्यवहारी बोगस व संदेहास्पद प्रतीत होने के कारण व वाहन में घोषित माल से अधिक माल लदा/परिवहनीत किये जाने के कारण वाहन को अधिनियम की धारा 78(4)(ए) के तहत निरुद्ध कर, परिवहनीत माल का भौतिक सत्यापन करवाने, प्रेषक व प्रेषिति व्यवहारियों के सत्यापन, माल के सही एवम् गंतव्य स्थान घोषित करने संबंधी वाहन चालक को नोटिस जारी किया गया एवम् उक्त के सत्यापन करवाने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रस्तावित कर, नोटिस जारी किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में मैसर्स भारतीय जनता परिवहन, जयपुर व मैसर्स शर्मा परिवहन कार्गो मूवर्स (प्रा.) लि., की ओर से भागीदार श्री छीतरमल शर्मा उपस्थित हुये जिनकी उपस्थिति में अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा माल का भौतिक सत्यापन करने पर बिल्टी क्रमांक 2507, 2503, 2510, 2515, 2504 व 2518 के जरिये परिवहनीत माल घोषित माल से भिन्न पाया गया, प्राईवेट मार्का व नगों की संख्या संबंधित बिल्टी में घोषित नगों की संख्या से भिन्न पायी गयी, जयपुर के माल की बिल्टी संख्या 8300 दिनांक 21.04.1999 से संबंधित नगों पर "टीजी" अंकित पाया गया एवम् यही मार्का बिल्टी क्रमांक 2506 दिनांक 21.04.1999 जो कि दिल्ली से उंझा के लिये बनायी गयी थी, पर भी पाया गया। इसी प्रकार सशक्त अधिकारी ने जांच कर, यह भी पाया कि बिल्टी क्रमांक 25/5 के पैकेज पर भी जी-टी/जयपुर अंकित पाया गया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने बिल्टी क्रमांक 3799, 2507, 2508, 2514, 2518, 2519, 2520, 2503, 2510, 2504, 2505, 2509 व 2513 के संबंध में दिल्ली के प्रेषक व्यवहारियों के संबंध में विभाग की कम्प्यूटर प्रणाली से जांच करने पर, बोगस पायी गयी। सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन चालक को जारी नोटिस की पालना में किसी प्रकार का कोई जवाब वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर, पुनः उक्त तथ्यों के आधार पर अधिनियम की धारा 78(2)(ए) का उल्लंघन करने के कारण अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपण हेतु व प्रेषक व प्रेषिति व्यवहारियों का सत्यापन करवाने के अभाव में अधिनियम की धारा 78(11) के तहत नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में श्री छीतरमल शर्मा ने स्वयम् को मैसर्स भारतीय जनता परिवहन, जयपुर का भागीदार होना प्रकट कर, मुख्य कार्यालय एच-67 आकड़मार्ग, बनीपार्क, जयपुर में होना प्रकट कर, दिल्ली, उंझा व अहमदाबाद में ब्रांच ऑफिस होना भी जाहिर किया गया। दिनांक 30.04.1999 को श्री एस.के.जैन,

अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर श्री शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित जवाब प्रस्तुत कर, कुछ व्यवहारियों के पंजीयन प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां प्रस्तुत कर, अधिनियम की धारा 78(5) व अधिनियम की धारा 78(11) के तहत आरोपित शास्ति के संबंध में अपीलार्थी सशक्त अधिकारी का क्षेत्राधिकार नहीं होना प्रकट किया गया । सशक्त अधिकारी द्वारा श्री एस.के.जैन द्वारा प्रस्तुत जवाब के क्रम में अधिनियम की धारा 78(2)(ए) का उल्लंघन करने के कारण अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपण हेतु व प्रेषक व प्रेषिति व्यवहारियों का सत्यापन करवाने के अभाव में अधिनियम की धारा 78(11) के तहत नोटिस जारी किया गया । जारी नोटिस की पालना में श्री छीतरमल शर्मा द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जवाब को ही जवाब मानने का कथन कर, प्रकरण का निस्तारण जवाब प्रस्तुत करने की दिनांक को ही करने का निवेदन किया गया । सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निवेदन को स्वीकार कर, पूर्व में प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार कर, अधिनियम की धारा 78(5) के तहत बिल्टी क्रमांक 3801, 2507, 2508, 2512, 2514, 2517, 2519, 2520, 2503, 2510, 2515, 2504 2505, 2509, 2513, 3799, 2511 व 2518 के जरिये परिवहनीत कर योग्य परचून माल कीमतन रु.7,39,534/— पर अधिनियम की धारा 78(5)के तहत शास्ति रु. 2,21,860/—, अधिनियम की धारा 78(2)(ए) का उल्लंघन करने के कारण अधिनियम की धारा 78(11) व 78(12) के तहत बिल्टी क्रमांक 3801 के जरिये कर योग्य माल कीमत रु.13,170/— पर कर रु.2,107/— व सरचार्ज रु.253/—, बिल्टी क्रमांक 2507, 2508, 2512, 2514, 2517, 2519, 2520, 2503, 2506, 2510, 2515, 2504 2505, 2509 व 2513 के कर योग्य माल कीमतन रु.5,86,269/— पर कर रु.70,352/— व सरचार्ज रु.8,442/— तथा बिल्टी क्रमांक 3799, 2511 व 2518 के कर योग्य माल कीमत रु. 14,0095/— पर कर रु.2,802/— व सरचार्ज रु.336/— कुल रु. 3,06,152/— आरोपित कर, आदेश पारित किया गया । उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यावारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी । जिससे व्यथित होकर सशक्त अधिकारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी । जिसे अधोहस्ताक्षरी की पीठ द्वारा जरिये दिनांक 30.10.2013 के अस्वीकार कर दिया गया । उक्त पारित निर्णय दिनांक **30.10.2013** के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा उक्त परिशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, इसमें परिशोधन चाहा गया है ।



3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. व्यवहारी की ओर से अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि पारित निर्णय दिनांक 30.10.2013 के जरिये व्यवहारी के विरुद्ध कायम शास्ति व कर राशि को पुनर्स्थापित किया गया है, जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है अतः पातिर आदेश दिनांक 30.10.2013 अधिनियम की धारा 33 के तहत परिशोधनीय है। व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस संबंध में लिखित बहस जो पत्रावली के संलग्न है, को आधार बनाकर अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित निर्णय को परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी। लिखित बहस निम्न प्रकार है:-

Because the order passed by learned Tax Board is violative of principles of natural justice as was done in great haste without looking to the judicila pronouncement in favour of the petitioneradn revenue biased manner.

Because the petitioner is only engaged in transportation of gods in the capacity of transporter. The duty of trasporter is only to transport goods from one place to another. Transport company is not involved in selling or buying business. They just attach the bills as provided by the dealer with the builties and work for commission. The transport company is not responsible for verifying the particulars about the dealers. All work of trasport company is bonafide.

Because the learned Bench failed to consider the fact theat the AssessingAuthority has passed the orderunder Section 29 of RST Act 1994 which provides for assessment of registered dealer, which in the present case will naot be applicable since section 29 of the Act provides for the assesement and no penalty is provided undersuch section. Hence the penalty under section 29 is per se illegal and ab-initio. Further Assessingauthority also passed and oeder under Section 78(5), 78(11) and 78(12) of RST Act 1994 treating the petitioner as deemed dealer which will not be applicable in the present case in as much as petitioner company is concerned. Therefore, applicability of penalty



as well as tax under different section for same transaction is not permissible under law.

Because the activities done by the petitioner is not covered in the ambit of business as defined in section 2(8) of Rajasthan Sales Tax Act, 1994. the petitioner is not engaged in any of the activity mentioned in the definition of business as the petitioner is not involved in any trade, commerce or manufacture.

Because as per provision of Section 24(4) defined in RST Act 1994 in term of Assessment wherein Assessment means determination of liability under the act and it includes Assessment on failure to deposit tax, self assessment, Assessment, Assessment in case of avoidance or evasion of tax, Escaped Assessment. Any liability even that of penalty imposed under the Act is covered under the ambit of Assessment.

Because the expression dealer has very well defined under clause 14 of section 2 of RST Act 1994. As per this section dealer means any person who carries on business in any capacity of buying, selling, supplying or distributing goods directly or other wise or making purchase or sales as defined in clause (38) for himself or other whether for cash or deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration and others mentioned in clause I to VI with explanation. Further the person indulged in the business of buying or selling and supply of goods for cash or deferred payments or for commission, remuneration or other valuable consideration can be a dealer. The petitioner is nowhere involved in the business of buying, selling, supplying of goods for any kind of consideration and at no stage in the case the Assessing Authority had proved any fact regarding the same. As the petitioner is only engaged in transportation of goods in the capacity of transporter/driver/owner of the vehicle, he is not a dealer. It is the duty of Assessing Authority to decide the facts that whether the petitioner is a dealer or not. It is

further submitted that under the rule Commissioner empowers to authorise any officer posted in the flying ?Squad to act as an Assessing Authority over such dealer as he may determine.

Because so far as Section 78 of RSt Act 1994 is concerned this Section deals for inspection of goods while in movement. Sub section 4 of said section empowers the State Government to authorize any officer to stop the vehicle or carrier in movement within his jurisdiction. The other subsections of the said Section empowers such officer to seize goods/impose penalty or take any other action. It is pertinent to mention herewith that Hon'ble Supreme Court has held in the matter of State v/s M/s M.M. Mathew reported in (1978) 42 STC 348 and Punjab and Haryana High Court in the case reported in (1981) 48 STC 369 held that Strong suspicion, strange coincidences and grave doubts cannot take the place of legal proof. Hence without any strong evidences considering the goods are related to dealers of Rajasthan is improper and accordingly detention of goods is invalid.

Because Section 78(5) (a) of RST Act 1995 states that

“Where any goods in movement, other than exempted goods are without any documents or are not supported by documents as referred to in sub section (2) or documents produced appears to be false and forged, the in charge of the check post of barrier or the officer authorised under section (4), may

Direct the owner or a person duly authorized by such owner or driver or the person in charge of the vehicle or carrier or of the goods not to part with the goods in any manner including by re transporting or re booking, till a verification is done or enquiry is made, which shall not take more than seven days.

That looking the position narrated above, since there is no power under section 78(5) (a) for detention of goods, hence, the detention memo issued was illegal and goods so detained were improper and without factual findings.

Because the learned Tax Board has grossly erred in not considering the fact that no notices were ever issued to all the consignor and consignee and no proper enquiry has been conducted upon all the consignor and consignee which were proved by the petitioner and also mentioned in the learned Deputy Commissioner (Appeals) order and further there has been no findings against the reasoned order passed by the learned Deputy Commissioner (Appeals)

- (A) Because the notice has been issued considering the statements given by driver. Initiation of proceedings as per statement given by the driver is improper. In support of the contention various Hon'ble courts in the matter of Mehta Road Carriers /v/s Rajasthan 21 TBR 201, Shikhar Shanker v/s Assistant commercial Taxes Officer (1997) 105 STC 40, Bansal Electric Company v/s ATO 1994 STO (1) 266, 2 RTJS 132, RTJS 199, held that the proceedings initiated are illegal and deserves to be set aside.

Because Hon'ble Rajasthan High Court in SB sales Tax Revision Petition No. 165/2011 CTO versus M/s Globe Transport Limited decided on 26-02-2013 has categorically held that

“Further, no enquiry whatsoever was made either from the purchaser(s) or the seller and, therefore, without further verification and merely on account of noticing certain deficiencies/errors, one cannot be held to be guilty and the CTO was not justified in imposing penalty. Had he interacted with the purchaser(s) as well as seller and had there any other discrepancy, after interaction, he could certainly come to the conclusion of imposition of penalty. As regards not stopping the vehicle, drivers as they are, being not educated, it might be possible that the driver of the vehicle would have got terrorized upon trying to stop the vehicle or chasing it by the flying squad and upon putting

indifferent question. So, the proper course, available with the CTO, was to make proper enquiry from the persons concerned (purchaser/seller) and merely on the basis of the statement of a poor driver and noticing certain discrepancies, without holding further enquiry in the matter from the concerned persons the penalty could not have been imposed.

Therefore, in the light of the above when transporter does not come under the purview of sale, the question of imposing tax or any other obligation does not arise.

Because the goods were carried from Delhi to Ahmedabad, Mumbai and other states and the petitioner has produced the details of the consignor and consignee along with their registration certificate namely (i) M/s Ashok Enterprises, Delhi (ii) M/s Sewa Ram Brij Gopal, Delhi, (iii) M/s Jagdish Prasad Shiv Kumar Agarwal, Delhi (iv) M/s Ramavtar Gupta and co, Delhi (v) M/s Swastik Enterprises,, Malad and (vi) M/s Jegesh Kumar Hargovind Das patel, Gujarat but despite of the fact of production of the documents no independent verification or enquiry was got conducted either from the consignor or the consignee but penalty was imposed on the petitioner which is in utter violation of the principles of natural justice.

Because no enquiry report was ever submitted to the petitioner so that the petitioner may prove its justification. It is wrong to say that time was granted to the petitioner to justify the case. No opportunity of cross examination was provided to the petitioner so that the petitioner may prove its case. Same is supported by the Hon'ble Supreme Court in the matter of Kalra Glue Factory v/s Sales tax tribunal reported in 66 STC 292 and by the Hon'ble High Court in the matter of Machilipatnam Central Consumers Co-Operative Stores Limited reported in (1988) 71 STC 153 and wherein it was held that "no opportunity given to notice for cross examine persons who furnished information is unjustified. The commercial tax officer failed to do this elementary enquiry. It was held that the noticee had लगातार..

discharge the initial burden that lay on him and in that view quashed the order". Further reliance is also placed on Mehta & Sons v/s CTO, Udaipur reported in (1992) 85 STC 59 (RHC), wherein it was submitted that the transport firm upon enquiry stated that records of delivery remained with that truck driver of company. The mere enquiry was not conclusive to reject the transaction made by the company.

Because Hon'ble Supreme Court has maintained the view of this Hon'ble Court in the case of State of Rajasthan and another Vs. M/s Sodhi Transport Co. and anr., reported in (2001) 10 Sales Tax Tday 219 (RHC, Jaipur) who has affirmed the order passed by the Rajasthan Taxation Tribunal (2001) 10 Sales Tax today 220(RTT) which has held as under:-

"If a vehicle was carrying goods from one State to another State through Rajasthan even with a view to evade tax in other State, the authority empowered under the Rajasthan Sales Tax, Act, 1954. for evasion of any tax taking place outside Rajasthan, the act had no application to it".

"The only question before us is whether the person in charge of the goods at the time of checking can be made liable for the payment of penalty in case he fails to produce the requisite documents. The principle laid down in Sant Lal's case (supra) was also followed by the Madhya Pradesh High Court at Jabalpur in Swastik Roadways and another v Commercial Taxes Officer, Barhanpur and Other, (1996) 103 STC 106. It was held that no duty on clearing and forwarding agents and transporters or common carriers to furnish to the Commissioner, information including statement of accounts in respect of the transactions of any dealer or to maintain the registers in the prescribed forms could be cast. No penalty could be imposed upon them in the case of contravention of such provisions."

"In this view of the matter Section 22A, RST Act not being applicable, confined as it is to the checking of evasion of tax under the RST Act in Rajasthan, the question of imposing

penalty under section 22A(7) RST Act in cases of goods transiting through Rajasthan cannot arise. The sales tax authorities of Rajasthan can, of course, stop and check any vehicle but if it contains goods coming from another State and bound for another State they can only insist and ensure that the goods leave Rajasthan.”

Because this learned Bench failed to appreciate the fact that in an identical matter, while disallowing the appeal in the matter of CTO, AE, Alwar versus Maa Ambey Cargo Movers, Ahmedabad, reported in 2012 (32) TUD 17(RTB), the Hon'ble DB of the RTB has held that:

- (1) “It is neither in accordance with law nor proper to draw the conclusion by the assessing authority that there was tax evasion merely on the basis that transporter and warehouse both at Bhilwara. The assessing officer has not complied with provision of Section 10 of the Act in as much as no enquiry has been made in finding of so called “Parchi” for Bhilwara.
- (2) The RTB has further held that it is neither proper nor legal that there being no verification of consignor of goods, penalty u/s 76(6) and levy of tax u/s 76(12) and 76(13) has been imposed owing to factual report.
- (3) The DC Appeals has allowed the appeal which is justified and hence there is no justification to interfere with his order”.

Looking to the above judgement the order passed by this Hon'ble Chair needs to be rectified.

व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त तर्कों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुये अधोहस्ताक्षरी की पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2013 को परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी ।

5. सशक्त अधिकारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2013 का समर्थन कर, कथन किया कि उक्त पारित आदेश में पीठ द्वारा

परिशोधन आवेदन पत्र संख्या : 13/2014/जयपुर
संचेतन मस्तिष्क से प्रकरण के गुणावगुण का विस्तृत विश्लेषण कर, अधोहस्ताक्षरी की एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 30.10.2013 को पारित किया गया है, जिसका पुनर्विलोकन कर, परिशोधन करना अधिनियम की धारा 33 की परिधि में नहीं है । जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने हालिया न्यायिक दृष्टांत मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 में छपा है, में यह अवधारित किया है कि परिशोधन में पुनर्विलोकन (review) शामिल नहीं है । अतः माननीय शीर्ष न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड, अधोहस्ताक्षरी की पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2013, व विद्वान अभिभाषक की लिखित बहस का अध्ययन व अवलोकन किया गया । विशिष्ट रूप से अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों का आद्योपांत गहन अध्ययन किया गया तथा विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधि का ससम्मान अध्ययन किया जाकर, अधिनियम की धारा 33 का स्पष्टीकरण का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया । अधिनियम की धारा 33 का स्पष्टीकरण इस प्रकार है:—

अधिनियम की धारा 33 का स्पष्टीकरण . — A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

उक्त स्पष्टीकरण के अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख की प्रकट भूल में कोई ऐसा आदेश आयेगा, जो उस समय विधिमान्य था जब वह पारित किया गया था जिसे भूतलक्षी प्रभाव से विधि के किसी संशोधन द्वारा या उच्चतम न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय या राजस्थान कर बोर्ड के किसी निर्णय द्वारा अविधिमान्य कर दिया जाये तो उक्त अधिनियम की धारा 33 की जद (Scope) में होगा परन्तु हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार की कोई परिस्थिति मौजूद नहीं है क्योंकि इस संबंध में कोई अभिलेख की प्रकट भूल नहीं हुयी है, न ही उक्त निर्णय को पारित करते समय विधि के किन्हीं प्रावधानों पर विचार करने से अधोहस्ताक्षर की पीठ से रहा है । अतः इस संबंध

परिशोधन आवेदन पत्र संख्या : 62 व 61 / 2010 / अजमेर
में अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों के आलोक में, पूर्व में संचेतन मस्तिष्क व खुली आंखों से पारित निर्णय का पुनर्विलोकन (review) करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37 जिसके प्रावधान अधिनियम की धारा 33 के तहत सादृश्य हैं, पर निम्न प्रकार अपना मत व्यक्त

किया गया है:- “The scope and ambit of the power which could be exercised under Section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said Section. Such a power is neither a power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right. (para-14).

इसी प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा अपने उक्त निर्णय में यह मत भी प्रतिपादित किया है कि: **“Section 37 of the Act 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face on the records and for which a reappreciation of the entire records is neither possible nor called for...”**(para-18)

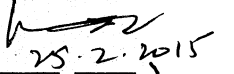
अतः अधोहस्ताक्षरी की पीठ द्वारा पारित आदेश जो दिनांक 30.10.2013 को संचेतन मस्तिष्क व खुले चक्षुओं से विधि के प्रावधानानुसार पारित किया गया है, को अधिनियम की धारा 33 के स्पष्टीकरण के प्रकाश में, परिशोधित करना विधिअनुकूल नहीं है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस में उठाये बिन्दुओं पर पारित आदेश दिनांक 30.10.2013 में भी विचार किया जा चुका है, एवम् पुनः वक्त बहस परिशोधन के संबंध में किसी प्रकार का कोई अन्य बिन्दु जो रिकॉर्ड पर परिलक्षित भूल से संबंधित हो, नहीं उठाया गया है। अतः विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों को सम्मान व्यक्त कर, विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत स.वा. क.अ. बनाम् मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692

/2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 में प्रतिपादित विधि को हस्तगत प्रकरण में लागू किया जाना न्यायसम्मत है। उक्त निर्णय में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों पर गहन विचार कर, यह व्यवस्था दी है कि धारा 33 की परिधि (Scope) में प्रकरण का पुनर्विलोकन नहीं आता। अतः अधोहस्ताक्षरी की पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2013 को संचेतन मस्तिष्क व खुली आंखों से विधि के प्रावधानानुसार पारित किया गया है, को परिशोधित करना विधिअनुकूल नहीं

है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यात्मक एवम् विधिक स्थिति के प्रकाश में, परिशोधन आवेदन पत्र विधिसम्मत एवम् न्यायोचित नहीं होने के कारण, अस्वीकार किया जाता है।

परिणामतः, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।


25.2.2015
(मदन लाल)
सदस्य